

प्रेषक,

एस० के० दास  
मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
सिंचाई विभाग, उत्तरांचल,  
देहरादून।

सिंचाई विभाग

दिनांक, देहरादून, 21 दिसम्बर / 06

विषय— सिंचाई विभाग के नियन्त्रणाधीन बीजापुर नहर पर स्थित 3  
घराटों को हिमालयन इन्वायरमैन्टल स्टडीज एण्ड कन्वर्जन  
ऑर्गेनाइजेशन (हैस्को) को 10 वर्ष हेतु लीज पर दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश  
हुआ है कि जनपद देहरादून में बीजापुर नहर पर स्थित तीन घराट  
कमरा गढ़ी घराट न०-01 एवं घराट न०-2 तथा डाकरा घराट न०-2,  
को अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड देहरादून के पत्र सं०  
4700/सि०ख० /दिनांक 6-12-06 के द्वारा दिये गये प्रस्तावानुसार  
अस्थायी तौर पर प्रति वर्ष का शुल्क 5000.00 रुपये प्रति घराट छी दर  
से निर्धारित करते हुए लीज अवधि अगले 10 वर्षों के लिए हिमालयन  
इन्वायरमैन्टल स्टडीज एण्ड कन्वर्जन ऑर्गेनाइजेशन (हैस्को) को  
आवंटित करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ  
प्रदान की जाती है कि उक्त अवधि में घराटों के अनुरक्षण एवं मरम्मत  
कार्य, जलकर, विद्युत कर, एवं किसी भी प्रकार के अन्य कर आदि के  
देयकों का भुगतान (हैस्को) द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा <sup>लीज</sup>अवधि  
समाप्त होने पर घराटों की लीज समाप्त होने वाली तिथि को यथास्थिति  
में ही सिंचाई विभाग को वापस करना होगा

## शर्तें

- 1- घराट को लीज पर देने की अवधि 10 वर्ष होगी। लीज अवधि समाप्त होने के उपरान्त उसके नवीनीकरण/पुनः लीज दिये जाने पर मूल विभाग स्वतन्त्र होगा, और उसे लीज शर्तों एवं लीज शुल्क में वृद्धि/परिवर्तन किये जाने का अधिकार होगा।
- 2- प्रत्येक घराट को लीज अवधि में चलाना आवश्यक होगा एवं लीज की अवधि के मध्य यदि लीज धारक घराट को नहीं चलाता है या बन्द कर देता है, तो उसे लीज अवधि (10 वर्ष) तक का लीज शुल्क का भुगतान करना होगा। इस आराय का लिखित शपथ पत्र लीज धारक से ले लिया जाय।
- 3- लीज धारक द्वारा घराट किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा, एवं लीज धारक बिना मूल विभाग की सहमति के घराट को किसी अन्य व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सोसाइटी/फर्म आदि को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
- 4- प्रत्येक घराट की लीज शुल्क रु0 5000/- प्रति वर्ष प्रति घराट होगी जो अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड देहरादून में प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।
- 5- घराट की लीज अवधि समाप्त होने के उपरान्त लीज धारक द्वारा घराट को यथास्थिति में सिंचाई विभाग को सौंपा जायेगा।
- 6- लीज धारक द्वारा घराट परिसर का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा और यदि किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर जांचोपरान्त शिकायत सही पायी जाती है तो लीज निरस्त कर दी जायेगी।
- 7- लीज धारक घराट परिसर को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने हेतु इसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन/परिवर्द्धन करने के लिए स्वतन्त्र होगा, किन्तु इसकी ऐतिहासिक पहचान को बनाये रखना होगा, तथा लीजधारक घराट परिसर को अधिक से अधिक उपयोगी एवं बहुउद्देशीय बना सकता है किन्तु इसके लिए मूल विभाग की सहमति लेनी आवश्यक होगी। लीज समाप्ति के पश्चात घराट, भूमि एवं उस पर किया गया निर्माण स्वतः ही मूल विभाग में निहित हो जायेगा। जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
- 8- घराट के संचालन एवं उसे बहुउद्देशीय बनाये जाने के कारण पेयजल / सिंचाई में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने एवं पर्यावरण पर



विपरीत प्रभाव पड़ने पर लीज समाप्त करने का अधिकार मूल विभाग को होगा।

- 9- लीज शर्तों /प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर या किसी अन्य विभाग/जन समुदाय के कारण विवाद होने पर जांचोपरान्त लीज समाप्त कर दी जायेगी। परन्तु उस दर का पूर्ण शुल्क लीज धारक से बसूल किया जायेगा।

उक्त आदेश राजस्व विभाग, उत्तरांचल शासन की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

एस० के० दास  
मुख्य सचिव।

स० 5703/11-2006-07(04)/04 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उत्तरांचल शासन को मा० मुख्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मा० मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 3- निजी सचिव, राज्य मंत्री, सिंचाई एवं ऊर्जा विभाग, उत्तरांचल शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तरांचल शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।
- 6- जिलाधिकारी, देहरादून।
- ✓ 7- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, उत्तरांचल देहरादून।
- 8- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड देहरादून को उनके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

श्री

(सुबर्न)

अधर सचिव।